



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2000/आश्विन 14, 1922

No. 655 ]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2000/ASVINA 14, 1922

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2000

का. आ. 916(अ).—केन्द्रीय सरकार, द्वारा पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (V) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिसूचना जिसे वह जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (V) के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के बाबत कोई आप्ठोप या सुझाव देना चाहता है, उसे लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ, सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110083 को भेज सकेगा।

## प्रारूप नियम

हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा तथा इसकी गुणता में सुधार लाने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है। इस अधिसूचना के कार्य क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पीढ़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तर काशी, उधम सिंह नगर, रुद्र प्रयाग, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल और चम्पावत जिले तथा पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला शामिल होंगे।

पर्यावरणीय दृष्टि से पहाड़ी नगरों का ठोस विकास सुनिश्चित करने के लिए हिमालय के क्षेत्रों में सभी भावी कार्यकलापों पर निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों को लगाने का प्रस्ताव है:

### पहाड़ियों पर शहरी क्षेत्रों की अवस्थिति योजना

- (i) ऐसे क्षेत्रों में जहाँ 30 डिग्री से अधिक ढलान है या ऐसे क्षेत्रों में जो परिसंकटमय जोन में आते हैं या स्प्रिंग लाइनों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में तथा उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात प्रथम क्रम प्रवाह वाले क्षेत्रों में कोई संनिर्माण नहीं किया जाना चाहिए।
- (ii) 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच ढलान वाले क्षेत्रों में या स्प्रिंग रिचार्ज क्षेत्रों या पुराने लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में ऐसे निर्बंधनों के साथ जिन्हें सक्षम स्थानीय प्राधिकारी विनिश्चित करे संनिर्माण कार्यों के लिए अनुज्ञा दी जानी चाहिए।
- (iii) टूरिस्ट रिजोर्ट्स, वाणिज्यिक कम्प्लेक्स और संस्थागत भवन ऐसे क्षेत्रों में अवस्थित होने चाहिए जहाँ जल और बिजली अधिशेष हो ताकि विद्यमान उपभोक्ताओं के अधिकार उनके पूर्व परामर्श किए बिना प्रभावित न हो।
- (iv) जहाँ क्षेत्र में कटाव से पारिस्थितिकीय नुकसान होता हो और पार्श्वस्थ क्षेत्रों की ढलान में अस्थिरता आती हो वहाँ ऐसे कटाव तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक कि ऐसे नुकसान से बचने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं किए जाते।
- (v) पर्यावरणीय और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए एक एकीकृत विकास योजना तैयार की जानी चाहिए। जिसमें पारिस्थितिकीय, संवेदनशील क्षेत्र, परिसंकटमय जोन, जल निकास नालियाँ, ढलान और उर्वरक भूमि भी है। अत्यधिक भूमिगत जल वाले क्षेत्रों में तीव्र संनिर्माण संबंधी कार्य नहीं किए जाने चाहिए।

### वर्षा जल का संग्रह

- (i) शहरी क्षेत्रों में भविष्य में सन्निर्मित किए जाने वाले सभी भवनों की छतों पर उनके कुर्सी क्षेत्र के अनुरूप वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था होनी चाहिए। आवासीय भवनों के मामले में 200 वर्ग मीटर से अधिक के कुर्सी क्षेत्र में इसकी न्यूनतम क्षमता 5 के.एल., 200 वर्ग मीटर या इससे कम वाले कुर्सी क्षेत्र में 2 के एल की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्यटक कम्प्लेक्स, होटल, शोपिंग कम्प्लेक्स जैसे वाणिज्यिक और संस्थागत भवनों और सरकारी भवनों के मामले में प्रति वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र में 0.01 घन मीटर की न्यूनतम क्षमता होनी चाहिए।

परंतु वाणिज्यिक और संस्थागत भवनों के लिए न्यूनतम मानक, ऐसे क्षेत्रों के भवनों पर भी लागू होंगे जो शहरी क्षेत्रों की सीमाओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

§ 118 जहां राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मानक पहले से ही अधिकृत किए गए हो, वहां ऐसे मानक पूर्व अग्रता वाले होंगे ।

§ 119 संस्थागत और वाणिज्यिक भवनों के विद्यमान जल आपूर्ति स्कीमों से जल नहीं लेना चाहिए जो स्थानीय गांवों या बस्तियों की जल आपूर्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं ।

§ 120 ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह परिसरों टैंकों और मण्डारण टैंकों और किसी अन्य साधन से किया जाना चाहिए ।

§ 121 स्प्रिंग जल निस्तारण में वृद्धि करने के लिए स्प्रिंग रिचार्ज क्षेत्रों में स्प्रिंग सेंसुअरी का विकास किया जाना चाहिए ।

§ 122 वर्षा जल नालियों के माध्यम से संग्रह किए गए वर्षा जल का उपयोग अपशिष्ट निपटन नालियों तथा सीवरों की सफाई के लिए किया जाना चाहिए ।

§ 123 ऐसे स्थानों में भूमिगत जल एक्स्चेंजर रिचार्ज छंछे निर्मित किए जाने चाहिए जहां ऐसे छंछों से क्लानों की स्थिरता को खतरा नहीं हो ।

### पहाड़ी सड़कें

पहाड़ी सड़कों के संनिर्माण के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देश :-

§ 124 हिमालय क्षेत्र में 5 कि.मी. से अधिक लम्बी विद्यमान सड़कों के विस्तार/ चौड़ा करने सहित किसी भी सड़क के संनिर्माण के लिए जहां यह तारकाली सड़कें न हों और पर्यावरणीय संपात निर्धारण अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजनार्थ जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार पर्यावरणीय संपात निर्धारण किया जाना चाहिए ;

- § 11§ जैव-इंजीनियरिंग तथा अन्य उपयुक्त तकनीकों के प्रयोग द्वारा सड़क काटने; आर-पार जल-निक्सी कार्यों तथा पुलियों के बनने से आस्थिर होने वाले पहाड़ी ढलानों को ठीक करने के लिए, सड़क के डिजाइन में प्रस्तावित सड़क की अनुमानित लागत में ऐसे उपायों की लागत की व्यवस्था की जानी चाहिए ;
- § 111§ संनिर्माण स्थलों से उपयुक्त एवं अभ्युक्त अवस्थानों में उचित रीति से मलबे के निपटन के लिए उपबंध किए जाने चाहिए ताकि इससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ; और ढेर की हुई सामग्री को जैव-इंजीनियरिंग एवं अन्य उपयुक्त तकनीकों से संसाधित किया जाना चाहिए तथा ऐसे उपायों पर होने वाली लागत को प्रस्तावित सड़क की अनुमानित लागत में शामिल किया जाना चाहिए ;
- § 1V§ जहाँ कहीं हाट मैक्स संयंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें बास्तियों से कम से कम 2 कि.मी. दूर स्थापित किया जाना चाहिए तथा स्थल के चारों ओर कम से कम 200 वर्ग मीटर क्षेत्र में वनस्पतियाँ नहीं छोनी चाहिए ।
- § 1V§ पुनर्वास योजना साहित उपयुक्त समग्र प्रबंधन तथा उपचार योजना के बिना पथर उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए तथा प्रबंधन योजना की लागत में स्थल के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए ;
- § 1VI§ सभी पहाड़ी सड़कों के किनारे पर्याप्त संख्या में नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए तथा इन नालियों को जल बहाव से होने वाले अवरोध से मुक्त रखा जाएगा ; यदि ऐसा नहीं किया जाता है और इससे पेसी हानि पहुँचती है जिसे अन्यथा रोका जा सकता था तो इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति अध-योजन/ नुकसानी के लिए दोषी होना चाहिए ; और जैव-इंजीनियरिंग तथा अन्य उपयुक्त तकनीकों के प्रयोग करके क्रास ड्रेन्स की उपयुक्तरूप से सफाई की जायेगी ताकि ढलानों की अस्थिरता को कम से कम किया जा सके ।
- § 1VII§ सड़क किनारे के नलों से होने वाले रन-आफ को, क्षेत्र में प्रकृतिक जल निक्षेप प्रणाली के साथ जोड़ा जाना चाहिए ।

- §V|||§ सड़क के संरक्षण के समय, धंश जोन और माने हुए भू-स्वलनग्रस्त क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ किसी कारणवश ऐसा करना संभव नहीं है वहाँ पूर्ण अस्थिरता बताते हुए सूचना दी जानी चाहिए और सम्बद्ध जेल्सियों को न्यूनतम करने के लिए पर्याप्त उपाय करने के बाद ही संनिर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए।
- §I×§ ऐसे क्षेत्रों के प्रारंभ और अंत को दर्शाने वाली सड़कों के साथ सभी धंश क्षेत्रों और भू-स्वलन क्षेत्रों के बारे में सूचना दी जानी चाहिए।
- §×§ पाटी में सड़कों के संरक्षण के लिए रिज को अधिमान दिया जाना चाहिए।
- §X|§ संरक्षण का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे वृक्षछादन की क्षति को कम किया जा सके।
- §×||§ नम क्षेत्रों से बचने के लिए दक्षिणी अथवा दक्षिण-पश्चिमी संरक्षण को अधिमान दिया जाना चाहिए।
- §×|||§ कटाव और भरण के व्यापक संतुलन और अनावश्यक कटाव से बचने के लिए सड़क का डिजाइन तैयार करते समय, समुचित मानक डिजाइनों का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- §×||||§ स्थानीय विकास के लिए मलबा सामग्री के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

[फा. सं. 14-8/2000-सी एस सी]

आर. एच. खन्ना, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th October, 2000

**S. O. 916(E).**— The following notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

**Draft Proposals**

It is proposed to issue a notification to protect and improve the quality of environment in the Himalayas, which would include the States of Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, and districts of Dehra Dun, Haridwar, Almora, Pithoragarh, Chamoli, Pauri Garhwal, Nainital, Uttar Kashi, Udham Singh Nagar, Rudra Prayag, Bageshwar, Tehri Garhwal and Champawat of Uttar Pradesh and Darjeeling district of West Bengal in the scope of this notification.

In order to ensure environmentally sound development of hill towns, the following restrictions and conditions are proposed for all future activities in the areas in the Himalyan region:

**Location Planning In Urban Areas in Hills**

- (i) No construction should be undertaken in areas having slope above 30° or areas which fall in hazard zones or areas falling on the spring lines and first order

streams identified by the State Governments on the basis of available scientific evidence;

- (ii) Construction should be permitted in areas with slope between  $10^{\circ}$  to  $30^{\circ}$  or spring recharge areas or old landslide zones with such restrictions as the competent local authority may decide;
- (iii) Tourist resorts, commercial complexes and institutional buildings should be located in areas with surplus water and electricity so as not to affect the rights of existing users without their prior consultation;
- (iv) Where cutting in an area causes ecological damage and slope instability in adjacent areas, such cuttings shall not be undertaken unless appropriate measures are taken to avoid such damages.
- (v) An integrated development plan may be prepared taking into consideration environmental and other relevant factors including ecologically sensitive areas, hazard zones, drainage channels, steep slopes and fertile land. Areas rich in ground water may not be diverted for construction activities.

### **Rain Water Harvesting**

- (i) All buildings to be constructed in future in urban areas should have provision for roof-top rain water harvesting commensurate with its plinth area with minimum capacity of 5 KL for plinth area above 200 sq.m.; 2 KL for plinth area of 200 sq.m. or below in case of residential buildings and minimum capacity of 0.01 cum per sq.m. of plinth area in case of commercial and institutional buildings such as tourist complexes, hotels, shopping complexes, and Government buildings:

provided that minimum standards for commercial and institutional buildings shall also apply to such buildings in areas not covered within the limits of urban areas;

- (ii) Where minimum standards have already been laid down by the State Governments, such standards shall take precedence;
- (iii) The institutional and commercial buildings should not draw water from existing water supply schemes which adversely affects water supply to local villages or settlements;
- (iv) In rural areas rain water harvesting should be undertaken through such structures as percolation tanks and storage tanks and any other means;

- (v) Spring sanctuary development should be undertaken in the spring recharge zones to augment spring water discharge;
- (vi) Rain water collected through storm water drains should be used to clean the waste disposal drains and sewers;
- (vii) Ground water aquifer recharge structures should be constructed wherever such structures do not lead to slope instabilities.

### **HILL ROADS**

Instructions to be issued by the State Governments for construction of Hill Roads:

- (i) For construction of any road in the Himalayan region of more than 5 km (including extension/widening of existing roads) length where the same may not be tarred roads and environmental impact assessment is otherwise not required; environmental impact assessment should be carried out in accordance with instructions to be issued for this purpose by the State Governments;
- (ii) Provisions should be made in the design of the road for treatment of hill slope instabilities resulting from road cutting, cross drainage works and culverts using bio-engineering and other appropriate techniques by including the cost of such measures in the cost estimate of the proposed road;
- (iii) Provisions should also be made for disposal of debris from construction sites in appropriate manner at suitable and identified locations so as not to affect the ecology of the area adversely; further, the dumped material should be treated using bio-engineering and other appropriate techniques and the cost of such measures should be included in the cost estimate of the proposed road;
- (iv) Wherever hot mix plants are used, they should be set up at least 2 km away from settlements and a minimum area of 200 sq.m. surrounding the site should be devoid of vegetation;
- (v) No stone quarrying should be carried out without proper overall management and treatment plan including rehabilitation plan and financial provision for rehabilitation of the site should be included in the cost of the management plan;
- (vi) All hill roads should be provided with adequate number of road side drains and these drains shall be kept free from blockage for runoff disposal; in the event that this is not done and this fact leads to damages that could otherwise have been prevented, the persons responsible should be liable for prosecution/damages; further, the cross drains shall be treated suitably using



bio-engineering and other appropriate technologies so as to minimise slope instability;

- (vii) The runoff from the road side drains should be connected with the natural drainage system in the area;
- (viii) Fault zones and historically land slide prone zones should be avoided during alignment of a road; where for any reason it is not possible to do so, notice should be given providing full justification and the construction should be carried out only after sufficient measures have been taken to minimise the associated risks;
- (ix) Notice should be given about all fault zones and land slide zones along the roads indicating the beginning and the end of such areas;
- (x) Ridge alignment should be preferred to valley alignment;
- (xi) Alignment should be selected so as to minimise loss of vegetal cover;
- (xii) South or South-west alignment should be preferred to avoid moist areas;
- (xiii) Appropriate design standards should be followed while designing the roads including mass balancing of cut and fill and avoidance of unnecessary cutting;
- (xiv) Encouragement should be provided for use of debris material for local development.

[F. No. 14-8/2000-CSC]

R. H. KHWAJA, Jt. Secy.

